

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया और केंद्र सरकार से राहत व पुर्नवास कार्यों के लिए सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास वित्तीय मामलों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज मंडी जिला के सराज में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां हुए नुकसान और राहत व पुर्नवास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों से भेंट की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सराज क्षेत्र को सात करोड़ रुपये तुरंत प्रभाव से जारी किए गए हैं और राजस्व अधिकारियों को सभी प्रकार के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए वन टाईम पॉलिसी लाने पर विचार करेगी। शांडिल ने कहा कि आपदा के बाद दुर्गम क्षेत्रों तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और थुनाग व जंजैहली क्षेत्रों में अभी तक 13 हजार 3 सौ 50 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है।

कुलदीप पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विधायी समितियां विधायिकाओं की रीढ़ हैं जो विस्तृत विचार विमर्श और प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाती हैं। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप पठानिया ने विधानमंडलों में अनुसंधान और सचिवालय सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने भ्रामक जानकारी के लिए विभागों को जिम्मेवार व जवाबदेह बनाने और मीडिया की भागीदारी व पारदर्शिता को मजबूत करने की जरूरत बताई। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने समिति प्रणाली के सुदृढीकरण विषय की समीक्षा के लिए सात राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की समिति का गठन किया है जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी शामिल हैं।

अवैध कटान

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिमला जिले में वन भूमि से कब्जे हटाने के लिए वन व राजस्व विभाग ने मुहिम को तेज कर दिया है। कोटखाई और कुमारसैन में वन भूमि पर बने बागीचों में सेब से लदे पेड़ों को काटा गया है जिससे सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने सेब कटान की कार्रवाई को अवैज्ञानिक करार दिया है और हाई कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ सरकार से कोर्ट में सही पक्ष रखने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि वन भूमि से कब्जे हटाने के नाम पर प्रदेश के किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। राकेश सिंघा ने राज्य सरकार पर इस संबंध में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा कि बागवान सेब के पौधों के कटान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जनानंदोलन किया जाएगा।

मौसम

प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में रुक-रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
